Objectives of National Literacy Mission

821. PROF. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the basic objectives of the National Literacy Mission;

(b) the details of the targets set under the Eighth Five Year Plan; State-wise;

(c) how far these targets have been achieved;

(d) the reasons for high rate of illiteracy in the Northern States; and

(e) the steps Government propose to take to tackle the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) The objective of National Literacy Mission (NLM) is to make 100 million people literate in the age-group of 15-35 by March, 1999 and to bring about full literacy by 2005.

(b) and (c) NLM is targetted to cover 345 districts by the end of the Eighth Five Year Plan. No State-wise targets have been set in this regard. District-wise Total Literacy Project proposals are sanctioned depending upon the level of preparedness in a particular district. As or date Total Literacy Camapaigns are being implemented in 414 districts and Post Literacy Campaigns in 174 districts.

(d) The reasons for high rate of illiteracy in the northern States, inter-alia, are dearth of committed volunteers, lack of literacy movements, widening gender bias against women, diverse socio-cultural factors etc.

(e) Some major steps which are being taken to tackle the situation are:

(i) Special meausres like sensitisation working for Collectors and the other officials and non-officials involved in literacy campaigns:

(ii) Organisation of workshop for writers and media personnel for sensitisation on literacy issues;

(iii) Launching of Operation Restoration in those districts which have not been able to achieve desired results;

(iv) Involvement of Panchayati Raj Institutions in the literacy programmes and sensitisation of Panchyati Raj functionaries as well as elected representatives;

(v) Special Cells for monitoring the literacy campaigns in these states.

निर्धन लड़कियों की शिक्षा हेतु योजना

822. श्रीमती आनन्दीबेन बेठाभाई पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

(क) क्या सरकार ने उन निर्धन लड़कियों की सहायता के लिए कोई योजना बनाई है जिन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी लड़कियों को सहायता प्रदान की गई और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1987 में आरम्भ की गई थी जिसमें 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के पढ़ाई बीच में छोड़ चुके स्कूली बच्चों को विशेष रूप से लड़कियों के लिए अपनी गति तथा सुविधानुसार प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए गए हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के 40: केन्द्रों को लड़कियों के लिए रखने का प्रावधान किया है। बालिका केन्द्रों को 90: केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जबकि सह-शिक्षा केन्द्रों के लिए 60: केन्द्रीय सहायता का प्रावधान रखा गया है।

इस समय यह योजना 21 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे लगभग 2.80 लाख केन्द्रों में लगभग 70 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 में लड़कियों के लिए लगभग एक लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गए थे जिनमें उन लगभग 25 लाख लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है जिनका प्राथमिक स्कूलों में या तो नामांकन हुआ ही नहीं था अथवा जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी।